



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2024—कार्तिक 17, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

क्र. ई-5-1159-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे (2013), कलेक्टर, जिला मऊगंज को दिनांक 16 से 25 अक्टूबर 2024 तक, दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 26, 27 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला मऊगंज की एक्स-इंडिया अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे (2012), कलेक्टर, जिला रीवा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मऊगंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला मऊगंज का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

क्र. ई-5-978-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल का दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 19, 20 एवं 26, 27 अक्टूबर 2024) के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र.ई-1-219-2024-5-एक.—श्री मोहित बुंदस, भाप्रसे (2011), प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम तथा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश, तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2024

क्र. ई-5-1059-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे (2009), सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के दिनांक 18 से 22 नवम्बर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 15, 16, 17 एवं 23, 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धनराजू एस. भाप्रसे (2009), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, वाणिज्यिक कर इंदौर तथा वि.क.अ.-सह-श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2024

फा. क्र. 4193-इक्कीस-ब-(एक) 2024.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009, में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 42 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

अनु. क्र.	सेशन न्यायाधीश / अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"42.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर	श्योपुर."

F. No. 4193-XXI-B (1)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department Notifications F. No.-1-1-88-XXI-B (1), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 6th November, 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for serial number 42 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Sessions Judge / Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“42.	I st District and Additional Sessions Judge, Sheopur	Sheopur.”.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2024

फा. क्र. 4183-इक्कीस-ब (एक) 2024.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
“27.	रायसेन	श्री महेश कुमार माली, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायसेन.”.

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 4183-XXI-(B-I)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following farther amendment in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013 dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20th September 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 27 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of special Judge
(1)	(2)	(3)
“27.	Raisen	Shri Mahesh Kumar Mali, IInd District and Additional Sessions Judge, Raisen.”.

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 4185-इक्कीस-ब (एक)-2024.—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 14 दिसम्बर 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) सहपठित मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (1) तथा उपधारा (1-ए) एवं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिश के परामर्श से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49), मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) एवं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता है, जिनका मुख्यालय कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	श्री आनंद कुमार सेहलाम, सत्ताईसर्वे, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सतना, कटनी, दमोह एवं सीधी.”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

F. No. 4185-XXI-B-(1)-2024.—In compliance of the order passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) 699/2016, Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Another dated 14th December, 2017 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), read with sub-section (1) and (1-A) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and also sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the State Government, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designate the Court of Additional Sessions Judge as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), the Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989) against the Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh as specified in column (2) of the table below having Headquarter at place specified in column (3) and having jurisdiction for the area comprising of revenue districts as specified in column (4) thereof, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Special Court	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	Shri Anand Kumar Sehlam, XXVII th District and Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Rewa, Shahdol, Umaria, Singrauli, Satna, Katni, Damoh and Sidhi.”

(2) This notification shall come into force with immediate effect.

फा. क्र. 4186-इक्कीस-ब-(एक) 2024.—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित जिले के लिए, कॉलम (3) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

सारणी		
अनु. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	सेशन न्यायालय (3)
“1.	अलीराजपुर	श्री काशीनाथ सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.”

F. No. 4186-XXI-B (One)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge mentioned in column (3), as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the Table given below to try the offences under the said Act, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Sessions Court (3)
“1.	Alirajpur	Shri Kashinath Singh, Principal District and Sessions Judge, Alirajpur.”

फा. क्र. 4187-इक्कीस-ब (एक) 2024.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 40 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी		
अनु. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (3)
“40.	सिंगरौली, बैड़न	श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, बैड़न.”

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 4187-XXI-(B-I)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. B(1) 3476-2013 dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20th September 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 40 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE		
S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
“40.	Singrauli Waidhan	Shri Varindra Kumar Tiwari, II nd District and Additional Sessions Judge, Singrauli, Waidhan.”

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 4191-2024-इक्कीस-ब-(एक).—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 की चयन सूची दिनांक 22 फरवरी, 2023 में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री जीवन लाल चौधरी (मेरिट क्र. 138) को माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा पर नियुक्ति के लिये अपात्र पाये जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री जीवन लाल चौधरी का नाम चयनित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 138 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

फा. क्र. 4191-2024-इक्कीस-ब-(एक).—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 की चयन सूची दिनांक 22 फरवरी, 2023 में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री आदर्श गोस्वामी पुत्र श्री महेन्द्र गोस्वामी (मेरिट क्र. 124) को माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा पर नियुक्ति के लिये अपात्र पाये जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री आदर्श गोस्वामी पुत्र श्री महेन्द्र गोस्वामी का नाम चयनित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 124 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

फा. क्रमांक 4192/21-ब(एक)/2024.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) तथा धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 2009/ 3835/21-ब(एक)/10, दिनांक 22 नवंबर, 2010 में, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करके, जो कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सिविल जिले के भीतर हैं तथा ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र की सीमाएं कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट सीमा तक होंगी और ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 74 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम	क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं जिनका क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय की सीमा तक होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74.	आगर-मालवा	आगर	आगर	राजस्व तहसील आगर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली पंचायतें / जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहां तक कॉलम (3) में यथाउल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।"

- 1) F.No. 4192/21-B(1)/2024. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 3 and section 4 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (4 of 2009), State Government, after consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 17(E)/2009/3835/21-B(One)/10, dated 22nd November, 2010 issued in this behalf, by establishing Gram Nyayalayas for Panchayat at intermediate level specified in column (3) of the table below within the civil districts specified in column (2) and the limits of the area to which the jurisdiction of the Gram Nyayalaya shall extend as specified in column (5) and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at the place specified in column (4) thereof. Namely:-

TABLE

S.No	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya	Local limits of the area to which the jurisdiction of Gram Nyayalaya extends
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
74.	Agar-Malwa	Agar	Agar	Panchayat / Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Agar including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends."

- 1) फा.क्रमांक 4202/21-ब (एक)/2024-उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (1-ए) के उपबंधों के अनुसार एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 49), मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता है, जिनका मुख्यालय कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी अर्थात्:-

सारणी

अनु. क्रमांक	विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय के स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विजय डांगी, उन्नीसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, रतलाम, बड़वानी, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, अलीराजपुर, नीमच, शाजापुर, मंदसौर एवं देवास।
2.	श्री स्वयं प्रकाश दुबे, इक्कीसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़, सागर, बैतूल एवं छिन्दवाड़ा।
3.	श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार, उन्नीसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी।
4.	श्री रूपेश कुमार गुप्ता, छब्बीसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, अनुपपूर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सतना, कटनी, दमोद एवं सीधी।”।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

F.NO.4202-XXI-B(1)/2024.—In compliance of the order passed on 14th December, 2017 by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) 699/2016, Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Others as per the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), as per the provisions of sub-section (1) and sub-section (1-A) of section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and as per the provisions of sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention.

of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the State Government, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designate the Court(s) of Additional Sessions Judge(s) as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act 1988 (49 of 1988), the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyaparan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) against the Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh specified in column (2) of the table below having Headquarters at places specified in column (3) and having jurisdiction for the area comprising of revenue districts as specified in column (4) thereof, namely:-

TABLE

S.No.	Name of Special Court	Place of Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)		(3)
1.	Shri Vijay Dangi, XXIX th District and Additional Sessions Judge, Indore	Indore	Indore, Ujjain, Dhar, Jhabua, Ratlam, Badwani, Burhanpur, Khandwa, Khargone, Alirajpur, Neemuch, Shajapur, Mandsaur and Dewas.
2.	Shri Swayam Prakash Dupey, XXI th District and Additional Sessions Judge, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Sehore, Vidisha, Raisen, Narmadapuram, Harda, Rajgarh, Sagar, Betul and Chhindwara
3.	Shri Dhirendra Singh Parihar, XIX th District and Additional Sessions Judge, Gwalior	Gwalior	Gwalior, Bhind, Morena, Sheopur, Datia, Guna, Ashoknagar, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna and Shivpuri
4.	Shri Rupesh Kumar Gupta, XXVI th District and Additional Sessions Judge, Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Rewa, Shahdol, Umaria, Singrauli, Satna, Katni, Damoh and Sidhi."

2. This notification shall come into force with immediate effect.

फा. क्र. 4204-2024-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री अशोक गुप्ता, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर में श्री विवेक कुमार गुप्ता के स्थान पर.
2	श्री अशोक कुमार शर्मा (जून.-2), द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ब्यावरा, जिला राजगढ़.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय देवास में कुमारी सरिता वाधवानी के दिनांक 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने पर.
3	श्री गंगाचरण दुवे, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सतना.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर में कुमारी नीता गुप्ता के दिनांक 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

पंजी क्र. 4209-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कमलेश कुमार इटावदिया का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर (म. प्र.)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2024

क्र. एफ-1-7-24-रा. स.-यू. ए.-1-1260.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर (म. प्र.) एतद्वारा, डॉ. विनोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, जी. एस. कालेज ऑफ कामर्स एण्ड इकानामिक्स, जबलपुर (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर का प्रथम कुलगुरु नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन (म. प्र.)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2024

क्र. एफ-1-8-24-रा. स.-यू. ए.-1-1262.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, क्रांतिसूर्य टंट्या भील, विश्वविद्यालय, खरगोन (म. प्र.) एतद्वारा, डॉ. मोहन लाल कोरी, (सदस्य, पी. सी. आई., नई दिल्ली) निदेशक, फार्मसी विभाग, आर. के. डी. एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए क्रांतिसूर्य टंट्या भील, विश्वविद्यालय, खरगोन का प्रथम कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना (म. प्र.)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2024

क्र. एफ-1-9-24-रा. स.-यू. ए.-1-1264.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना (म. प्र.) एतद्वारा, डॉ. किशन यादव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग एवं शोध केन्द्र, बुंदेलखण्ड पी. जी. कालेज, झांसी (उ. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना का प्रथम कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

क्र. 7240-आर. डी. एम.-2024.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2(क)-15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, समिति की बैठक दिनांक 14 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपात्तरण करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से :—

एक— नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सरणी के) कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं तथा

दो — सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करते हैं।

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है। (1)	ग्राम / स्थानीय क्षेत्र का नाम (2)	पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है। (3)
थाना अमलाई, जिला शहडोल	1 पड़रिया	चौकी केशवाही, जिला शहडोल

केदार सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क्र. 3023-अ भू-अ-03-2024

नर्मदापुरम, दिनांक 30 सितम्बर 2024

सतपुडा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम के वनग्रामों के निवासियों को विस्थापित कर वन विभाग की वन भूमि पर बसाया गया है संदर्भित पत्र के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के तहत वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार भारत शासन से पुनर्वास हेतु स्वीकृत ग्राम एवं वनग्रामों के निर्वनीकरण कर वन ग्रामों के डिजिटल नक्शे एवं अधिकार अभिलेख बनाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

अतः नीचे दर्शित विस्थापित वनग्रामों को वन ग्राम से राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

अनुसूची

क्र.मा.क.	जिला	तहसील	पूर्व वनग्राम का नाम	वन विभाग से प्राप्त क्षेत्रफल (हे०) में	नवीन राजस्व ग्राम का नाम	वनग्राम से राजस्व ग्राम बनये जाने वाले ग्राम की चतुर्सीमाएं				वन परिक्षेत्र
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	
1	2	3	4	5	6	7				8
1	नर्मदापुरम	इटारसी	पोडार	240.000	नया पोडार	सहेली	कास्दा रैयत	हिरण चापडा	कास्दा रैयत	घोघरा
2	नर्मदापुरम	इटारसी	रतिबदर	160.000	नया रतिबदर	चौकी पुरा	सिल वारी	भाड़ भूड	बल चापडा	कास्दा
3	नर्मदापुरम	इटारसी	मल्लूपुरा	40.000	नया मल्लूपुरा	साकई	बैतूल	एन.एच. 69	रेल्वे एवं कालाआ खर की जमीन	कास्दा
4	नर्मदापुरम	इटारसी	साकई भाग-1	40.000	नया साकई भाग-1	भाड़भूड	मल्लू पुरा	एन.एच. 69	कालाआ खर	कास्दा
5	नर्मदापुरम	इटारसी	मालनी भाग-4	98.000	नया मालनी भाग-4	बांदरी	मलोथर	पारछा	बांदरी	बांदरी
6	नर्मदापुरम	माखननगर	बदकछार	200.000	नया बदकछार	रोरी घाट	जंगल सरकार	चूरना	परास पानी	सोहागपुर सामान्य
7	नर्मदापुरम	इटारसी	मल्लूपुरा भाग-4	29.034	नया मल्लूपुरा भाग-4	ढाबा कला	बडी नहर/ भडम चीखली	मलोथर / बडी नहर	हतेड नदी	मकोडि या
8	नर्मदापुरम	इटारसी	खामदा भाग -2	14.232	नया खामदा भाग-2	अमाड़ा	महेन्द्र वाडी	अमाड़ा	महेन्द्रवा डी	अमाड़ा
9	नर्मदापुरम	इटारसी	रतिबदर (टोला)	12.000	नया रतिबदर टोला	चौकी पुरा	साकई	एन.एच. 69	भाड़ भूड	कास्दा
10	नर्मदापुरम	माखननगर	खामदा भाग-1	41.600	नयाखामदा भाग-1	नया जाम	जंगल सरकार	काकडी एवं जाम की भूमि	कासिया का मेढा	पहनत ला

क्र.मा.क.	जिला	तहसील	पूर्व वनग्राम का नाम	मूल विभाग से प्राप्त क्षेत्रफल (हे०) में	नवीन राजस्व ग्राम का नाम	वनगांव से राजस्व ग्राम बनये जाने वाले ग्राम की चतुर्सीमाएं				वन परिक्षेत्र
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	
1	2	3	4	5	6	7				8
11	नर्मदापुरम	माखन नगर	गालनी भाग-5	58.400	नया मालनी भाग-5	डोल रिया सुर्द	रोड	अजनडा ना	कांसि या का मेढा	पहनतला
12	नर्मदापुरम	इटारसी	नया झालई भाग-1	67.000	नया झालई भाग-1	साकई	जमानी	मांदी खोह	झालई गांव	नीलगढ़
13	नर्मदापुरम	माखन नगर	सुपलई भाग-3	100.000	सुपलई भाग-3	मोहगाव	जंगल (शास.)	माना	जंगल (शास.)	बागडा
14	नर्मदापुरम	माखन नगर	मल्लूपुरा भाग-3	66.000	मल्लूपुरा भाग-3	नया धाई	वन कक्ष क० 193	धमनिया	डोम	डूडादेह
15	नर्मदापुरम	इटारसी	सुपलई भाग-1	50.000	सुपलई भाग-1	महेन्द्र वाडी	पी०एफ ०/179 वनक्षेत्र	पी०एफ ०/179 वनक्षेत्र	टांगना	खोरी
16	नर्मदापुरम	इटारसी	सुपलई भाग-2	110.000	सुपलई भाग-2	पारछा	पी०एफ ०/174 वनक्षेत्र	टांगना	हथेड़ नदी	खोरी
17	नर्मदापुरम	इटारसी	खामदा भाग - 3	87.000	खामदा भाग - 3	अमाडा	टांगना	खटामा	महेन्द्र वाडी	खोरी
18	नर्मदापुरम	इटारसी	माना भाग-2	270.000	माना भाग-2	जमानी	जमानी	जमानी	जमानी	खोरी

सोनिया मीना, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 नवम्बर 2024

क्र. 6879-वरिष्ठ लिपिक-2024.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-08-2023-एक-4, दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2024, दिन शुक्रवार, गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 132-वरिष्ठ लिपिक-2023, दिनांक 5 जनवरी 2024 के द्वारा छिन्दवाड़ा जिले के लिए दिनांक 1 नवम्बर 2024, दिन शुक्रवार को घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाकर इसके स्थान पर दिनांक 12 नवम्बर 2024, दिन मंगलवार देवउठनी एकादशी / तुलसी विवाह का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

उपरोक्त अवकाश कोषालय / उप-कोषालयों पर लागू नहीं होगा.

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

क्रमांक/PCCF/7/0123/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला- सिंगरौली
वनमण्डल- सिंगरौली

तहसील- सरई
वन परिक्षेत्र- पश्चिम सरई

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	बजारी	बजारी	शासकीय राजस्व भूमि (पहाड़)	3200/1041 (भाग)	45.00	<p>उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से आरक्षित वनखण्ड बजारी (बी) 11 के मुनारा क्रमांक 35 तक कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>आरक्षित वनखण्ड बजारी (बी) 11 के मुनारा क्रमांक 35 से 32 तक आरक्षित वनखण्ड की सीमा।</p> <p>आरक्षित वनखण्ड बजारी (बी) 11 के मुनारा क्रमांक 32 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 तक कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 10 एवं 1 तक कृत्रिम वन सीमा।</p>
योग					45.00 हेक्टेयर	

क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निम्न प्रकरण:-

क्र.	ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक	प्रभावित वनभूमि	कलेक्टर का आदेश	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक
1.	FP/MP/WATER/418049/2023	4.9659	कलेक्टर जिला सिंगरौली का आदेश दिनांक 20.09.2023 से कुल 45.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि प्रदाय की गयी है।	06/05/2024
2.	FP/MP/WATER/418064/2023	4.9114		25/07/2024
3.	FP/MP/WATER/463438/2023	22.6448		भविष्य में समयोजन हेतु
4.	FP/MP/WATER/156042/2023	12.0145		
		44.5366	45.00 हेक्टेयर	

उक्त प्रकरणों में मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई की स्वीकृत पाईप लाईन बिछाने में प्रभावित 44.5366 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 45.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 34/अ-20(3)/23-24 सिंगरौली दिनांक 20.09.2023 से हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर जिला-सिंगरौली के आदेश क्रमांक 34/अ-20(3)/23-24 सिंगरौली दिनांक 20.09.2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

क्र. /PCCF/7/0123/2024-FLR-PCCF : भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक /PCCF/7/0123/2024-FLR-PCCF का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal the 28th October 2024

No./PCCF/7/0123/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas. Specified in the schedule below, Subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that state Government from time to time.

SCHEDULE

District - Singrauli

Tahsil - Sarai

Forest Division - Singrauli

Forest Range - West Sarai

S. No.	Name of proposed Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No. Old/New	Area (In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Banjari	Banjari	Govt. Revenue Land (Pahad)	3200/1041 (part) Total:-	45.00 45.00	North:- Artificial forest boundary from pillar no. 1 to 4 of proposed protected forest block. East:- Artificial forest boundary from pillar no. 4 to 7 of proposed protected forest block. South:- Artificial forest boundary from pillar no. 7 of proposed protected forest block to pillar no. 35 of reserved forest block Banjari (B) 11. Forest boundary from pillar no. 35 to 32 of reserved forest block Banjari (B) 11. Artificial forest boundary from pillar no. 32 of reserved forest block Banjari (B) 11 to pillar no. 9 of proposed protected

						forest block.
						West:- Artificial forest boundary from pillar No. 9 to 10 and pillar No.1.

A. Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's :-

S.No.	Case No.	Affected Forest Land	Collector order	Govt. of India Senction
1.	FP/MP/WATER/418049/2023	4.9659	Collector District Singrauli	06/05/2024
2.	FP/MP/WATER/418064/2023	4.9114	order dated 20.09.2023	25/07/2024
3.	FP/MP/WATER/463438/2023	22.6448	total 45.00 hectares of non-forest land has been provided.	To be adjusted in future
4.	FP/MP/WATER/156042/2023	12.0145		
	04	44.5366	45.00 ha.	

In lieu of 44.5366 hectare affected forest land in above sanctioned cases of Pipeline Laying of Project Implementation unit, Jal Nigam Maryadit, Madhya Pradesh. For compensatory afforestation 45.00 hectare Non forest land has been transferred/ mutated in favour of forest Department, Madhya Pradesh vide Collector District Singrauli order No. 34/अ-20(3)/23-24 Singrauli, Dated 20.09.2023.

2. Detail of other Reasons – Nil

B. The Khasra wise details of recorded right on the above land as per order no. 34/अ-20(3)/23-24 of collector Singrauli, Dated 20.09.2023 are as Under:-

1. **Individual Rights :-** There are no individuals Right on the said land.

2. **Community Rights :-** There are no Communities Right on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 21 अक्टूबर 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2023-24-15507.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

स.क्र.	भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	खण्डवा	पुनासा	केलवाबुजुर्ग	0.74 हेक्टर एवं मकान पक्का-02	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह (म.प्र.).	औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न.वि. संभाग क्र. 32, बड़वाह के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2023-24-15508.- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 2964-कार्य-भू-अर्जन-2024, बड़वाह, दिनांक 2 सितम्बर 2024 प्रस्तुत कर औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण कुल रकबा 0.74 हेक्टर भूमि एवं मकान पक्का 02 का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है :-

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खंडवा	पुनासा	18	केलवाबुजुर्ग	0.74 हैक्टर एवं मकान पक्का-02	औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न.वि. संभाग क्र. 32, बड़वाह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 अक्टूबर 2024

प्र.क्र. 15-अ-82-2024-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मझगवाँ	निजी भूमि रकवा 65.168 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा 155.788 हे. कुल रकवा 220.956 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत पवई बांध की जल भराव क्षमता 01 मीटर बढ़ाये जाने से (339.50 मी. से 340.50 मी. होने पर) प्रभावित क्षेत्र में आने वाली भूमि के भू-अर्जन हेतु (प्रथम पूरक प्रस्ताव) धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 25 अक्टूबर 2024

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. भू-अर्जन-2024-3680-प्र. क्र. 10-अ-82-24-25.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्सन डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम जमालपुरा पटवारी हल्का क्रमांक 26	314 / 1	0.65
कुल योग				0.65

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बरेली, दिनांक 27 सितम्बर 2024

क्र. 3143-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र. 0008-अ-82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12 फरवरी 2014 सात-2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमि

धारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा :-

अनुसूची

स.क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	गडरवास	नरेन्द्र सिंह आ. रामसिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम गडरवास	64/4/2/1	1.114	0.067	कार्यपालन यंत्री, बारना बायी नहर, संभाग बाडी.	बरना परियोजना की दायीं मुख्य नहर एम-2/ डी-आरबीसी नवीन सब माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम गडरवास.

संतोष मुदगल, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

प्र.क्र. 0013-अ-82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

1-भूमि का विवरण :-

(क) जिला	- सीहोर
(ख) तहसील	- भैरुदा
(ग) ग्राम	- मंडी
(घ) 1.120 हेक्टेयर भूमि	

अनुसूची (2)

क्र. (1)	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम (2)	सर्वे नंबर (3)	कुल रकबा (4)	अर्जित रकबा (5)	रिमार्क (6)
1.	पोकारमितुल कुमार अरविन्द, पिता पोकार अरविन्द, जाति पटेल, पता- जियापर नखत्राना, कच्छ, गुजरात भूमिस्वामी.	252/228/2	0.720	0.720	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	निर्मला पुत्री मूरत सिंह, पत्नी रविशंकर, जाति अहीर, पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि-स्वामी	227 / 2	1.248	0.400	
कुल योग		2	1.968	1.120	

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील भैरुदा, जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

घट्टिया, दिनांक 26 अक्टूबर 2024

प्रारूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

क्र. भू-अर्जन-2024-1564-प्र.क्र. 003-अ-82-NH-2024-25.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. भू-अर्जन-प्र.क्र. -003-अ-82-NH-2024-25, दिनांक 6 सितम्बर 2024 द्वारा राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 सितम्बर 2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार, कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	घट्टिया	ग्राम अम्बोदिया, पटवारी हल्का क्रमांक 25	4 75	0.25 0.47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			74	0.02
			72	0.15
			71	0.57
			77	0.57
			69	1.47
			68 / 1	1.70
			68 / 2	2.40
			78	0.54
			79	0.18
			70	0.47
			86 / 1	0.40
			86 / 2	1.60
			86 / 3	0.61
			67	1.77
			58	0.46
			59	0.16
			87	0.47
			90	0.96
			89	0.43
			52	1.64
			45	0.05
			41	0.81
			53	0.20
			40	0.35
			39	0.25
			38	1.20
			37	1.01
			35	0.32
			42	0.62
			36	0.06
			228 / 1	0.59
			228 / 2	0.67
			229 / 1	0.50
			317 / 1 / 1	0.10
			316 / 1	0.24
			316 / 3	0.10
			298 / 1	0.15
			298 / 2	0.18
			298 / 3	0.06
			299	0.24
			296 / 1 / 1	0.20
			296 / 1 / 2	0.10
			296 / 2 / 1	0.63
			296 / 2 / 2	0.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			297	0.84
			295 / 2 / 1	0.31
			295 / 2 / 2	0.06
			294 / 2	0.54
			293	1.72
			292 / 1	0.11
			292 / 2 / 1	0.52
			292 / 2 / 2	0.48
			292 / 3	0.26
			292 / 4	0.26
			291	0.19
			278	0.07
			279 / 2	0.04
			277 / 1	0.14
			277 / 2	0.34
			277 / 3	0.29
			294 / 1	0.05
			51 / 1	0.04
			66 / 1	0.09
			76	2.66
			57	0.19
			56	1.00
			91	0.19
			60	0.23
			61	4.42
			92 / 1	0.73
			64	0.36
			55	0.35
			54	0.40
			292 / 2	1.18
			287	1.10
			316 / 2	0.11
			81	0.25
			308	0.05
			2	0.22
			82	0.52
			145	0.10
			275	0.13
			405	0.25
			कुल योग	47.21

राजाराम करजरे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

प्रारूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

क्र. भू-अर्जन-2024-1565-प्र.क्र. 002-अ-82-NH-2024-25.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. भू-अर्जन-प्र.क्र. -002-अ-82-NH-2024-25, दिनांक 6 सितम्बर 2024 द्वारा राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 सितम्बर 2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार, कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	घट्टिया	ग्राम बड़वई, पटवारी हल्का क्रमांक 26	126 / 2	0.55
			126 / 3 / 1	0.19
			126 / 3 / 2	0.05
			162	0.78
			163	0.11
			164	0.19
			127 / 2	0.72
			161 / 1	0.42
			161 / 2	0.23
			160 / 1	0.23
			169 / 1	0.40
			159 / 3	0.70
			159 / 2 / 1	0.93
			159 / 2 / 2	0.30
			158 / 2	0.06
			171 / 1	0.17
			172 / 1	0.41
			174	0.14
			310	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			311 / 1	0.06
			291 / 1	0.03
			291 / 2 / 1	0.015
			291 / 2 / 2	0.015
			291 / 3	0.03
			292	0.11
			294	0.09
			297	0.02
			298	0.11
			299	0.28
			301	0.10
			302	0.04
			303	0.05
			304	0.06
			305	0.08
			306 / 1	1.12
			306 / 2	0.55
			300	0.08
			308	0.30
			267	0.14
			279 / 1	1.01
			279 / 3	1.00
			276 / 1 / 1	0.70
			276 / 1 / 2	0.18
			268	0.12
			273 / 1	1.18
			275 / 1	0.25
			274 / 2	0.24
			274 / 1	0.03
			271	0.59
			269	2.19
			247	1.36
			248	0.94
			246 / 1	1.10
			242 / 1	2.13
			249	0.51
			270 / 1	0.47
			245 / 1	0.30
			243	0.04
			239	0.25
			240	0.55
			346 / 1	0.16
			125	0.34
			169 / 2	0.31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			157	0.10
			173	0.25
			170	0.47
			171 / 2	0.16
			172 / 2	0.13
			169 / 2	0.02
			311 / 2	0.21
			289	0.10
			290	0.03
			168 / 2	0.02
			309	0.08
			279 / 2	0.08
			275 / 2	0.07
			276 / 2	0.15
			273 / 2	0.05
			277	0.14
			288	0.10
			241	0.70
			245 / 2	0.08
			323	0.45
			346 / 2	0.07
			कुल योग	29.36

राजाराम करजरे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 नवम्बर 2024

नस्ती क्र. एल.ए.-16142-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0002-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अमलपुरा, सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा, सतवाड़ा, बड़गांवमाली, नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सिवना	1.5664	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा.	अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल.ए.-16143-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0002-अ-82-2024-25.- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खण्डवा की ओर से पत्र क्र. 3396-त.शा.-मार्ग-अमलपुरा-सांवखेडा नहाल्दा मार्ग, दिनांक 5 सितम्बर 2024 कलेक्टर महोदय, जिला खण्डवा को प्रस्तुत कर बताया कि अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य लोक हित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ये छूट प्रदान करता हूँ :-

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खण्डवा	खण्डवा	66	सिवना	1.5664	अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.

नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल.ए.-16144-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0004-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अमलपुरा, सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा, सतवाड़ा, बड़गांवमाली, नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	नहाल्दा	1.76	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा.	अमलपुरा सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा सतवाड़ा बड़गांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल.ए.-16145-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0004-अ-82-2024-25.- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खण्डवा की ओर से पत्र क्र. 3396-त.शा.-मार्ग-अमलपुरा-सांवखेड़ा नहाल्दा मार्ग, दिनांक 5 सितम्बर 2024 कलेक्टर महोदय, जिला खण्डवा को प्रस्तुत कर बताया कि अमलपुरा सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा सतवाड़ा बड़गांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य लोक हित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनूप कुमार सिंह कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खण्डवा	खण्डवा	83	नहाल्दा	1.76	अमलपुरा सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा सतवाड़ा बड़गांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.

नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र. एल.ए.-16146-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0003-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित अमलपुरा, सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा, सतवाड़ा, बड़गांवमाली, नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सांवखेड़ा	0.88	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा.	अमलपुरा सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा सतवाड़ा बड़गांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र. एल.ए.-16147-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0003-अ-82-2024-25.- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खण्डवा की ओर से पत्र क्र. 3396-त.शा.-मार्ग-अमलपुरा-सांवखेड़ा नहाल्दा मार्ग, दिनांक 5 सितम्बर 2024 कलेक्टर महोदय, जिला खण्डवा को प्रस्तुत कर बताया कि अमलपुरा सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा सतवाड़ा बड़गांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य लोक हित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनूप कुमार सिंह कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.मै.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खण्डवा	खण्डवा	67	सांवखेडा	0.88	अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.

नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल.ए.-16148-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0005-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अमलपुरा, सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा, सतवाडा, बडगांवमाली, नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. मै.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सतवाडा	0.86	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा.	अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल.ए.-16149-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0005-अ-82-2024-25.- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खण्डवा की ओर से पत्र क्र. 3396-त.शा.-मार्ग-अमलपुरा-सांवखेडा नहाल्दा मार्ग, दिनांक 5 सितम्बर 2024 कलेक्टर महोदय, जिला खण्डवा को प्रस्तुत कर बताया कि अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य लोक हित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनूप कुमार सिंह कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खण्डवा	खण्डवा	68	सतवाडा	0.86	अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.

नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्र. 10-भू-अर्जन-प्र.क्र. 08-अ-82-2023-24-4981.

— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला-शहडोल

(ख) तहसील-गोहपारू

(ग) ग्राम-कनवाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)-0.411 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1) रकबा (हेक्टेयर में) (2)

97	0.070
112/1	0.040
112/2	0.040
100/1	0.040
100/2	0.048
101	0.012
540/2	0.161

कुल रकबा . . 0.411

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - श्यामडीह-कनवाही मार्ग के किमी 3/2 में सोन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, उपसंभाग, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 0005-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-चिखल्दाखुर्द-8353

बैतूल, दिनांक 11 सितम्बर 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

**अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)**

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल नगर	चिखल्दाखुर्द	0.934	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल, बैतूल @ नागपुर	इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

**अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)**

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	भगवती बेवा बाबूलाल	92/1	0.091	0.010
2	कैलाश पिता शंकरलाल	94/1	0.111	0.063
3	कैलाश पिता शंकरलाल	96/1	1.005	0.100
4	सूर्यकांत पिता मिश्रीलाल	116/1	2.902	0.022
5	संगीता पत्नी सुनील सालम	118/1	0.228	0.011
6	लुथिया बाई बेवा भैयालाल	120/1	0.073	0.015

7	प्रहलाद पिता बालमुकुंद	121/1/1	0.495	0.042
8	अज्जादी बेवा मुकुंदी	121/2/1	0.495	0.042
9	सेवकराम पिता नानकराम	132/2/1	0.196	0.031
10	भगवती बेवा बाबूलाल	132/1/2	0.073	0.073
11	भगवती बेवा बाबूलाल	132/1/1	0.024	0.023
12	अरूण कुमार पिता चंद्रागोपाल	133	0.271	0.045
13	यशोदा बेवा श्रीराम	131/6	1.136	0.026
14	गणेश पिता रामप्रसाद	131/7	1.137	0.027
15	मथुराबाई पिता काशीराम	135/3	0.405	0.036
16	कौशल्या पति दशरथ	134	0.439	0.368
कुल योग			9.081	0.934

- 1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-916-भू-अर्जन-24

सीधी, दिनांक 10 अक्टूबर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न हो कर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4)उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

ग्राम	:-	पडरिया
तहसील	:-	बहरी
जिला	:-	सीधी

निजीभूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रकबा 0.7730 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	635/1/15	0.0420	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु।
2	635/1/14	0.0020		
3	635/1/27	0.090		
4	635/4	0.0480		
5	635/1/17	0.060		
6	635/1/19	0.0600		
7	635/1/21	0.0420		
8	635/2	0.0960		
9	635/1/11	0.0720		
10	635/1/13	0.0600		
11	635/1/3/24/1	0.0240		
12	635/1/3/24/3	0.01500		
13	635/1/3/24/2	0.0100		
14	635/1/5	0.0240		
15	635/1/25	0.0200		
16	635/1/3/1	0.0420		
17	635/3	0.0420		
18	635/5	0.0240		
योग-	18 किता	0.7730 हे.		

- भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
- उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितवद् कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यह सूचना एवं सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.-0009-अ-82-2023-24

छतरपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची-

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला छतरपुर

(ख) तहसील राजनगर

(ग) नगर/ग्राम-टिकुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.625 हे०

क्रं.	भूमिस्वामी का नाम/पिता/ पति का नाम/पता	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा
1	2	3	4
1	सचिन पिता भगवानदास त्रिवेदी	1587/5/2/1/1/1/1/1	0.282
2	निधि पुत्री भगवानदास त्रिवेदी	1587/5/2/1/1/1/2	0.020
3	ओमकार पिता ब्रजगोपाल अवस्थी	1587/5/2/1/1/1/2	0.020
4	नीरेंद्र पिता सुखनंदन अवस्थी	1587/5/2/1/1/2	0.010
5	मानिकलाल पिता बसंते रैकवार	1587/5/2/1/2	0.010
6	भगवानचरन पिता नत्थू त्रिवेदी	1587/5/2/2	0.010
7	हिमांशी पुत्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा	1650/2/2	0.020
8	जशोदा पत्नि गोकुल अहिरवार	1650/2/1/2	0.020
9	दीपक पिता जम्मा अहिरवार	1650/2/1/1/2	0.020
10	पार्वती पुत्री गोकुल अहिरवार	1650/2/1/1/1/2	0.020
11	अच्छेलाल पिता मथुरा अहिरवार हिस्सा 362/645, गोकुल पिता मथुरा अहिरवार हिस्सा 273/645 अरुण प्रताप सिंह पिता केशव सिंह हिस्सा 10/645	1650/2/1/1/1/1	0.385
12	राधे पिता रामदास कौंदर	2539/1	0.170
13	ध्रुव पिता राजीव कुमार अवरस्थी	2428/2	0.020
14	विपेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह	2428/1/2	0.010
15	वैभव सिंह पिता नारायण सिंह राय	2428/1/1/2	0.010
16	अजय पिता रामस्वरूप तिवारी	2428/1/1/1/2	0.020
17	अरविन्द पिता गोकुल पाल	2428/1/1/1/1/4	0.015
18	ओमप्रकाश पिता गोकुल पाल	2428/1/1/1/1/3	0.015
19	रमिया देवा मथुरा राकेश भागराज पिता मथुरा केशकली फूला पिता रामदयाल प्रेमबाई मानकुंवार पुत्री हरी देवकली पत्नि हीरालाल हिस्सा 198/286 अनारी पिता गोकुल पाल हिस्सा 22/286 ओमप्रकाश पिता गोकुल पाल हिस्सा 22/286 अरविन्द पिता गोकुल पाल हिस्सा 22/286 मुन्नीबाई पत्नि रामचरन हिस्सा 11/286 गणेश कुमारी पुत्री रामचरन हिस्सा 11/286	2428/1/1/1/1/1	0.025
20	अनारी पिता गोकुल पाल	2428/1/1/1/1/2	0.015
21	अनन्तराम पिता भुमानीदीन ब्रा०	1611/4/8	0.020
22	संदीप पिता भरत कुमार अग्रवाल	1611/4/9/2	0.018
23	समीना बानो पत्नि मवीन खान	1611/4/9/1/1/1/2	0.015
24	इमामन बानो पत्नि नसीम खलीफा	1611/4/9/1/1/1/1/2	0.015
25	आभा पत्नि संदीप अग्रवाल	1612/1/2/6	0.025

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता/पति का नाम/पता	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा
1	2	3	4
26	प्रदीप कुमार पिता प्रागीलाल ब्रा0	1612/3/2	0.020
27	दिलीप कुमार पिता प्रागीलाल ब्रा0	1612/3/1	0.020
28	रामकृष्ण पिता प्रागीलाल ब्रा0	1612/3/3	0.020
29	महेश पिता रामस्वरूप विश्वकर्मा	1619/1/2	0.020
30	चंदूलाल पिता रमजुवा अहिरवार	1619/1/1/1/1/1/2	0.010
31	हरप्रसाद पिता रमजुवा अहिरवार	1619/1/1/1/1/1/3	0.010
32	ब्रजगोपाल राजाराम अवस्थी	1619/1/1/1/1/1/4	0.010
33	बद्रीप्रसाद पिता राजाराम अवस्थी	1619/1/1/1/1/1/5	0.010
34	बबलू पिता रामस्वरूप कुशवाहा	1619/1/1/1/1/2	0.010
35	अंकित पिता अशोक कुमार यादव	1619/1/1/1/2	0.010
36	आदिल खान पिता अशरफ खान	1619/1/1/2	0.010
37	विपेन्द्र पिता नारायण सिंह सूर्यवंशी	1619/1/1/2	0.010
38	करन्जुवा रमजुवा पिता उमरौवा अहिरवार	1619/1/1/1/1/1/1	0.150
39	भगतू पिता मत्थू आदिवासी	1805/1/2/2/1/1/2	0.025
40	रामरती पुत्री रामेश्वर आदिवासी	1771/8	0.010
41	सीता पुत्री रामेश्वर आदिवासी	1771/7	0.010
42	बबलादेवी रामरती पुत्री लक्ष्मी प्रसाद कौंदर	1771/9	0.010
43	सरुआ लल्लीबाई पिता भुनुवा मल्लू पत्नि छिद्दी विनोद, मनोज, दिब्बी, दरबारी, पप्पू कला, सोना, रामा, कूता पिता छिद्दी जाति चमार	1643/1/1	0.015
44	आनंदी, राकेश, प्रकाश पिता महादेव वीरेन्द्र भरत पिता महादेव पार्वती, पानबाई शिवकली पुत्री महादेव लल्लीबाई बेवा महादेव जाति चमार	1643/1/2	0.015
45	सत्यवती पत्नी राम किशोर त्रिवेदी	1587/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.010
46	शकुन्तला पत्नी रामसजीवन ब्रा0	1587/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.010
कुल किता- 46 :-			1.625
43	सरुआ लल्लीबाई पिता भुनुवा मल्लू पत्नि छिद्दी विनोद, मनोज, दिब्बी, दरबारी, पप्पू कला, सोना, रामा, कूता पिता छिद्दी जाति चमार	1643/1/1	0.015
44	आनंदी, राकेश, प्रकाश पिता महादेव वीरेन्द्र भरत पिता महादेव पार्वती, पानबाई शिवकली पुत्री महादेव लल्लीबाई बेवा महादेव जाति चमार	1643/1/2	0.015
45	सत्यवती पत्नी राम किशोर त्रिवेदी	1587/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.010
46	शकुन्तला पत्नी रामसजीवन ब्रा0	1587/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.010
कुल किता- 46 :-			1.625

2. सार्वजनिक प्रयोजन - ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्र.क्र.-0010-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची-

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- पहाड़ीबावन्

(ख) तहसील राजनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.60 हे०

क्रं.	भूमिस्वामी का नाम/पिता/पति का नाम/पता	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा
1	बाबूलाल नाबालिग पिता दरवारीलाल संरक्षक दरवारीलाल जाति काछी हिस्सा रकवा 741/1071 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 330/1071	526/1	0.020
2	मुन्ना पिता गंगवा बसोर जाति बसोर हिस्सा रकवा 900/1000 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 100/1000	595/1/6	0.260
3	बलीराम पिता दरवारी जाति काछी हिस्सा रकवा 742/1072 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 330/1072	526/2	0.020
4	अशोक कुमार पिता जमना प्रसाद जाति ब्रा० हिस्सा रकवा 100/400 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 300/400	525/7/1	0.030
5	पूरन पिता जगदीश जाति ब्रा० हिस्सा रकवा 1/3 रवि पिता जगदीश जाति ब्रा० हिस्सा रकवा 1/3 अनीता पिता जगदीश जाति ब्रा० हिस्सा रकवा 1/3	525/5/1	0.270
कुल किता- 05 :-			0.60

2 सार्वजनिक प्रयोजन-ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-0011-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची-

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- पीरा

(ख) तहसील राजनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.237 हे०

क्रं.	भूमिस्वामी का नाम/पिता/पति का नाम/पता	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा
1	शान्ती पत्नी रामजी प्रसाद मिश्रा वर्षा पत्नी नीतेश पाण्डेय	1140/2	0.010
2	रामअवतार पिता कामता प्रसाद ढीमर	1215/2/1/1	0.007
3	राममिलन तनय बाबूलाल ढीमर	1215/2/2	0.007
4	बालकिशुन तनय बाबूलाल ढीमर	1215/2/3	0.009
5	अरुण कुमार तनय परमलाल ब्राम्हाण	1236	0.009
		1241/2	0.026
6	राजाराम पिता परमलाल ब्राम्हाण	1241/1	0.028
7	विजय कुमार पिता मानिक चन्द्र जैन	1267/2/3	0.070
8	कमलेश कुमार तनय स्वरूपचन्द्र जैन	1267/1/2/1	0.012
9	पुष्पेन्द्र पिता स्वरूपचन्द्र जैन	1267/1/2/2	0.011
10	पदमनी पुत्री दरवारी लाल पति मूलचन्द्र मिश्रा	1327/6/5/1	0.013
11	श्री बिहारी जू मंदिर जिलाध्यक्ष महोदय छतरपुर	1285	0.010
12	श्री बाबूलाल तनय भगवान दास दुबे निवासी टिकुरी	1202/3/2	0.025
	कुल किता- 12 :-		0.237

- सार्वजनिक प्रयोजन-ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-0012-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची-

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला छतरपुर

(ख) तहसील राजनगर

(ग) नगर/ग्राम- सपोंहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.263 हे०

क्रं.	भूमिस्वामी का नाम/पिता/पति का नाम/पता	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा
1	मंगलदीन पिता सरजू जाति तेली हिस्सा रकवा 1316/1370 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 54/1370	118/4	0.020
2	(शासकीय) सुकरतिया रैकवार बेवा बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (शासकीय) ग्यासी रैकवार पुत्र बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (शासकीय) भागीरथ रैकवार पुत्र बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (शासकीय) बहादुर रैकवार पुत्र बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (शासकीय) बिन्नाबाई रैकवार पुत्री बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (शासकीय) राजाबाई रैकवार पुत्री बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय)	162	0.025
3	मैयादीन पिता मंगी हिस्सा रकवा 1488/1500 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 12/1500	273/1	0.018
4	पुनिया बेवा पिता भइया जाति तेली हिस्सा रकवा 3047/3647 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 600/3647	116/2/1	0.200
कुल किता- 04 :-			0.263

- सार्वजनिक प्रयोजन-ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-0013-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची-

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- राजपुर

(ख) तहसील राजनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.043 हे०

क्रं.	भूमिस्वामी का नाम/पिता/पति का नाम/पता	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा
1	काशीराम पिता मनकू चमार	112/2	0.080
2	प्रेमलाल पिता रावन अहीर	116/5/2	0.196
3	चरन, प्रेमलाल, रामनरेश पिता सुकियाँ कौंदर	779	0.010
4	शोभालाल पिता वोडा कौंदर हि. 1/2 रामकिशुन पिता बोडा कौंदर हि. 1/2	111/1/1	0.050
5	विन्द्रावन लक्ष्मन मिजाजी हीरालाल पिता कमतू अहीर जसौदा बेवा कमतू अहीर	282/1	0.035
6	विन्द्रावन पिता कमतू अहीर	291/3	0.400
7	खसरा पर नाम नहीं है।	112/3	0.252
8	नन्हे भैया पिता खुमना अहिरवार	776/1/3	0.020 (कुआँ)
	कुल किता- 08 :-		1.043

2 सार्वजनिक प्रयोजन-ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पार्थ जैसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

क्र.-14197-भू-अर्जन-2024

हरदा, दिनांक 10 अक्टूबर 2024

चूँकि म.प्र. शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा को, खिरकिया नहर की 6 एल माईनर निर्माण के लिए आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अंतर्गत भू-अर्जन की आवश्यकता होने से निम्न विवरण में वर्णित भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 अंतर्गत निर्धारित “प्ररूप-ख” में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है, कि नीति अंतर्गत भूमि, विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला-हरदा, तहसील खिरकिया, ग्राम चौकड़ी, कुल अर्जित रकबा 2.308 हे.।

क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)			अन्य संपत्ति
				सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
✓1	राकेश पिता लक्ष्मीनारायण, चौकड़ी	184/2	2.044 हे.	0.190 हे.	0	0.190 हे.	निरंक
✓2	शंकरलाल पिता मोहनलाल कुड़मी, चौकड़ी	191/1	3.325 हे.	0.079 हे.	0	0.079 हे.	निरंक
✓3	जगदीश पिता घनश्याम विश्नोई, चौकड़ी	224	1.081 हे.	0.079 हे.	0	0.079 हे.	निरंक
✓4	सोना बेवा उमराव, कैलाश, गोकुल पिता उमराव, अशोक कुमार पिता भागीरथ, चौकड़ी	225/1/2	0.996 हे.	0.048 हे.	0	0.048 हे.	निरंक

5	उमेश पिता सत्यनारायण विश्णोई, चौकड़ी	246	4.824 हे.	0.174 हे.	0	0.174 हे.	निरंक
6	रामप्यारी विधवा रामनारायण, चुन्नी, भवानी, भगू, करण, भागीरथ, नन्हेलाल पिता सेवाजी माली, चौकड़ी	245	2.744 हे.	0.149 हे.	0	0.149 हे.	निरंक
7	शिवी पिता प्रकाशचंद ब्राम्हण, भोपाल	414	2.023 हे.	0.109 हे.	0	0.109 हे.	निरंक
8	गौरीशंकर, श्यामलाल, विवेक पिता हरीशंकर, चौकड़ी	416	1.619 हे.	0.090 हे.	0	0.090 हे.	निरंक
9	प्रकाशचंद पिता मांगीलाल, ब्राम्हण, भोपाल	417	4.444 हे.	0.142 हे.	0	0.142 हे.	निरंक
10	नर्मदाप्रसाद, रामेश्वर, लक्ष्मीनारायण पिता रामनारायण, रामेश्वर पिता रूखड़या, चंदई, इन्दरबाई पुत्री पंचम, चौकड़ी	421	0.069 हे.	0.012 हे.	0	0.012 हे.	निरंक
11	भगवती बेवा नर्मदाप्रसाद, नीतूबाई पुत्री नर्मदाप्रसाद, रामौतार पिता नर्मदाप्रसाद, निवासी चौकड़ी	589/2, 589/3	1.011 हे.	0.151 हे.	0	0.151 हे.	निरंक
12	विभा पत्नी प्रकाशचंद, ब्राम्हण भोपाल	578	1.064 हे.	0.036 हे.	0	0.036 हे.	निरंक
13	सुमना पत्नी गौरव, ब्राम्हण, भोपाल	576	1.380 हे.	0.122 हे.	0	0.122 हे.	निरंक
14	शिवी पिता प्रकाशचंद ब्राम्हण, भोपाल	574	2.792 हे.	0.072 हे.	0	0.072 हे.	निरंक
15	मुरलीधर पिता मोती, चौकड़ी	575/4	0.392 हे.	0.126 हे.	0	0.126 हे.	निरंक
16	नंदकिशोर, प्रमोद, प्रवीणकुमार पिता	548/1, 548/2	3.161 हे.	0.048 हे.	0	0.048 हे.	निरंक
	रामकिशन, चौकड़ी						

17 ✓	कमलाबाई पुत्री रामकरण बलाही, चौकड़ी	547/1	1.465 हे.	0.102 हे.	0	0.102 हे.	निरंक
18 ✓	श्रीराम पिता कुंजीलाल, धीरज, नीरज पिता श्रीराम कुड़मी, चौकड़ी	546/1, 546/2, 546/3	3.573 हे.	0.084 हे.	0	0.084 हे.	निरंक
19 ✓	हीरालाल, भारत पिता भूराजी, मुरलीधर, हरीशंकर पिता मोती, चौकड़ी	545/1, 545/2, 545/3, 545/4	3.576 हे.	0.175 हे.	0	0.175 हे.	निरंक
20 ✓	भगवानसिंह, चैनसिंह पिता शंकर, बसंतीबाई पुत्री शंकर, आशा, उषा पुत्री देवीसिंह, अनारसिंह, इन्द्रनारायण, कलीबाई पिता सुखराम, चौकड़ी	546/4	1.190 हे.	0.320 हे.	0	0.320 हे.	निरंक
	योग :-		42.773 हे.	2.308 हे.		2.308 हे.	

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया एवं कार्यपालन
यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आदित्य सिंह, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

सीहोर, दिनांक 25 अक्टूबर 2024

प्रकरण क्रमांक 0003/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :- 1

परियोजना का नाम :- पार्वती वृहद परियोजना

भूमि का वर्णन

(क) जिला - सीहोर

(ख) तहसील - श्यामपुर

(ग) ग्राम - बर्री

(घ) क्षेत्रफल - 5.604 है.

—: अनुसूची :- 2

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (निजी) हे.में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	✓ राजेश पुत्र प्रेमनारायण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	289/98/1/1	2.217	✓ 0.848	
2	✓ बदामबाई पत्नी भगवतसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	5/2	1.618	✓ 0.030	
		6/3/1	0.509	✓ 0.080	
3	✓ सुनीता पत्नी मुकेशकुमार जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/5/1	1.554	✓ 0.040	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (निजी) हे.में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
4	सीमाबाई बेवा विश्राम सिंह अनुराग ना बा पुत्र विश्राम सिंह महिमा ना बा पुत्री विश्रामसिंह संरक्षक माता स्वयं जाति देशवाली पता बर्री श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/3/1/1	1.614	0.101	
5	सतीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	290/98/2/1	0.682	0.040	
6	ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली. पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	19/1/2	0.162	0.120	
7	भागीरथ पुत्र दयाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3, मेहताब बाई बेवा दयाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3, विक्रम पुत्र दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	11/2/1	1.106	0.115	
8	रामस्वरूप पिता बंशीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	21/1	0.534	0.050	
		20/1	1.307	0.180	
9	परमानंद पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	29/2/1	0.668	0.180	
10	योगेन्द्रसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	6/4/1	0.878	0.030	
		6/2/1	0.122	0.020	
11	हाकमसिंह पिता अमरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	11/1/1	0.587	0.175	
12	राजेशकुमार पिता भगवानसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	16/2/1/1	2.849	0.160	
13	राकेश पिता राधेश्याम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/11	0.781	0.135	
14	पुरुषोत्तम पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	17/3/1	0.641	0.045	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (निजी) हे.में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
15	ओमप्रकाश पिता रुग्नाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	17/2/1	0.549	0.329	
16	संजयकुमार पिता मोतीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/8	0.809	0.020	
17	भारतसिंह पिता रामचंद जाति देशवाली पता नि० ग्राम श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	289/4	1.100	0.282	
18	कृष्णमोहन पिता गोपीलाल जाति देशवाली पता नि० ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/6	1.145	0.340	
19	मुरारीलाल पिता घनश्याम जाति देशवाली पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	289/2/5/2	0.277	0.089	
20	विक्रमसिंह पिता गीतालाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/9	1.073	0.101	
21	रुखमणीबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	289/98/3	1.214	0.350	
22	पंकज पिता गीतालाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/12	1.073	0.085	
23	सरजनसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	3/2	4.088	0.788	
24	श्रीकिशन पिता परसराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/1/1	1.368	0.050	
25	बनबारी मनोज पिता हेमराज जाति देशवाली पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	289/98/2/2/1	0.798	0.447	
		289/98/2/7	0.502	0.038	
26	मोहनसिंह पिता घनश्याम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	289/2/5/1	0.277	0.142	
27	घीसीबाई बेवा अमरसिंह ओमप्रकाश गोपाल पुत्र अमरसिंह प्रेमबाई गायत्रीबाई पुत्री अमर सिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भाग समान सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	289/2/6-98	0.405	0.177	
28	राकेश पिता अवधनारायण जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	9/10	0.101	0.017	
कुल योग :-		32	32.608	5.604	

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/ तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 0002/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची - 1 :-

परियोजना का नाम :- पार्वती वृहद परियोजना

भूमि/परिसंपत्ति का वर्णन

- (क) जिला - सीहोर
(ख) तहसील - श्यामपुर
(ग) ग्राम - मानपुरा
(घ) क्षेत्रफल - 17.472 है. भूमि, 30.40 व.मी.
परिसंपत्ति

—: अनुसूची - 2 :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (निजी) हे.में	रिमार्क
1	प्रहलादसिंह पिता सोदानसिंह जाति राजपूत पता मानपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48/3	0.809	0.490	
2	प्रेमबाई बेवा धुरीलाल अर्जुनसिंह पदमसिंह हरिनारायण जगदीश पुत्रगण धुरीलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	119/1	0.077	0.050	
3	नर्बदाप्रसाद मदनलाल गोरिलाल पुत्र गबरूलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	27/6	2.023	2.023	
4	मांगीलाल पिता बुधराम जाति चमार पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	273/63/5/2/3	0.001	0.001	
		273/63/5/2/2	1.210	1.210	
		273/63/5/2/1	1.214	1.214	
5	जगदीश पिता सरदार जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/1/1	0.069	0.069	
		86/1/1	0.361	0.260	
		100/1	0.110	0.110	

6	भारतसिंह पिता बदतलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	149/1	0.344	0.344		
		120/1	0.085	0.075		
		274/69/2	0.307	0.126		
7	लाखनलाल पुत्र लीलाकिशन कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	21/2/2	0.667	0.467		
8	ओमप्रकाश पिता रामगोपाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	137/1/1	0.403	0.403		
9	कलीबाई बेवा रामगोपाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	137/2/1	0.180	0.180		
10	छोटाराम पिता धनलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	27/7/6	0.506	0.506		
11	भगवानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति सुतार पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	231/22/1	0.748	0.748		
12	विनोद पुत्र लाखनलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	231/22/2	0.429	0.429		
13	गंगाबाई पत्नी लाखनलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	231/22/3	0.117	0.117		
14	प्रोतमसिंह उर्फ राहुलसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	232/23	1.287	1.287		
15	रेखाबाई पत्नी अशोक जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	28/7	1.619	1.619		
16	शान्तिबाई बेवा बन्नीप्रसाद जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	67/3	1.214	1.214		
17	फूलबाई पुत्री काशीराम जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	67/4	1.214	1.214		
18	कलाबाई बेवा नारान जाति सुतार पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/5	3.237	0.760		
19	शैलेन्द्रसिंह पुत्र अनिरुद्धसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	198/1/1/1	0.398	0.198		
		188/1	0.501	0.501		
20	चन्द्रभान पुत्र हरिप्रसाद जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	188/2	0.493	0.373		
21	आदेशकुंवर सीमाकुंवर पुत्री भगवान सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम चांदबड़ भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	188/3	0.494	0.070		
		198/1/2	2.193	0.980		
22	अशोक कुमार पुत्र मांगीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	198/1/4	1.821	0.300		
23	रमेशचंद्र पिता ज्ञानक सिंह जाति कुम्हार पता निवासी हसनपुरतिनोनिया सीहोर मध्य प्रदेश	273/63/5/4	0.134	0.134		
कुल योग :-		31	24.265	17.472		
परिसंपत्ति						
सं क्र	नाम कृषक, पिता का नाम	खसरा नम्बर	पक्के मकान की लम्बाई मीटर में	पक्के मकान की चौड़ाई मीटर में	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	रिमार्क
1	शैलेन्द्र सिंह पिता नेत सिंह जाति राजपूत	4/3/2	7.60	4	30.40	गैर रहवासी पक्का मकान छत आर सी. सी. की है।

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/ तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 अक्टूबर 2024

प्रकरण क्रमांक/ 08 /अ-82 वर्ष 2024-25, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा- 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- | | | |
|---------------|---|-----------------|
| (क) जिला | — | पन्ना |
| (ख) तहसील | — | पन्ना |
| (ग) ग्राम | — | बिल्हा |
| (घ) क्षेत्रफल | — | 14.450 हैक्टेयर |

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
01	694	0.020	निजी भूमि
02	695	0.050	निजी भूमि
03	704	0.600	निजी भूमि
04	705	0.420	निजी भूमि
05	707	0.040	निजी भूमि
06	691	0.200	निजी भूमि
07	706	0.150	निजी भूमि
08	709 / 1	0.435	निजी भूमि
09	710 / 1	0.760	निजी भूमि
10	709 / 2	0.495	निजी भूमि
11	710 / 2	0.500	निजी भूमि
12	711	0.350	निजी भूमि
13	713	1.310	निजी भूमि
14	715 / 2	0.190	निजी भूमि
15	718 / 1 / 1	0.530	निजी भूमि
16	719 / 1 / 1	0.480	निजी भूमि
17	718 / 1 / 2	0.540	निजी भूमि
18	719 / 1 / 2	0.470	निजी भूमि
19	729	1.380	निजी भूमि
20	730	0.320	निजी भूमि
21	727 / 1	2.000	निजी भूमि
22	737	1.450	निजी भूमि
23	741 / 1	0.900	निजी भूमि
24	741 / 2	0.160	निजी भूमि
25	743	0.200	निजी भूमि
26	739	0.500	निजी भूमि
किता - 26		14.450	

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- बड़खेरा तालाब योजना अंतर्गत बाँध के डूब क्षेत्र अंतर्गत आने वाली भूमियों के भू-अर्जन हेतु भूमि अर्जन धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम बिल्हा, तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग पन्ना में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक/ 07 /अ-82 वर्ष 2024-25, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा- 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला — पन्ना
(ख) तहसील — पन्ना
(ग) ग्राम — हरदुआ
(घ) क्षेत्रफल — 09.890 हेक्टेयर

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
01	341	0.400	निजी भूमि
02	366	1.900	निजी भूमि
03	347	0.490	निजी भूमि
04	351	0.050	निजी भूमि
05	352	1.000	निजी भूमि
06	355	0.860	निजी भूमि
07	350	0.600	निजी भूमि
08	353	1.200	निजी भूमि
09	354	0.050	निजी भूमि
10	342	0.420	निजी भूमि
11	343	0.300	निजी भूमि
12	345 / 1	0.150	निजी भूमि
13	345 / 2	0.490	निजी भूमि
14	348	0.830	निजी भूमि
15	346	0.480	निजी भूमि
16	356 / 1	0.400	निजी भूमि
17	356 / 2	0.270	निजी भूमि
	किता — 17	09.890	

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- बड़खेरा तालाब योजना अंतर्गत बाँध के डूब क्षेत्र अंतर्गत आने वाली भूमियों के भू-अर्जन हेतु भूमि अर्जन धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम हरदुआ, तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-9982-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0039-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 2 नवम्बर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	20.002 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- नागदा
(ग) ग्राम	:- निम्बोदिया खुर्द
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 20.002 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	7/1	0.121		
2	10	0.028		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	11/1	0.070	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	11/2	0.175		
5	15/1	0.255		
6	15/2/1	0.450		
7	15/2/2	0.393		
8	15/3	0.005		
9	57/1	0.019		
10	76	0.747		
11	74/1	0.315		
12	74/2/1	0.125		
13	78	0.287		
14	71/1	0.227		
15	71/2	0.327		
16	72	0.080		
17	80/2	0.001		
18	87/1	0.211		
19	87/2/1	0.095		
20	87/2/2	0.249		
21	86/1	0.413		
22	86/2	0.282		
23	86/3	0.414		
24	85/1/2	0.246		
25	85/1/3	0.696		
26	85/1/7	0.192		
27	89/2/1	0.017		
28	89/2/2	0.044		
29	88	0.305		
30	95/1/1	0.083		
31	208/1	0.349		
32	208/5	0.589		
33	208/6	0.294		
34	204	0.440		
35	203/1/1	0.191		
36	203/1/2	0.039		
37	203/1/3	0.003		
38	203/2	0.054		
39	239/1/1	0.015		
40	239/3	0.242		
41	239/4	0.226		
42	239/5	0.282		
43	239/6	0.748		
44	239/7	0.422		
45	239/8	0.379		
46	239/9	0.363		
47	199/1	0.007		
48	199/2	0.001		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
49	241	0.640	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
50	259	0.500		
51	258/1	0.480		
52	258/2	0.490		
53	258/3	0.490		
54	240	0.620		
55	253/4	0.853		
56	253/5	0.001		
57	253/7	0.275		
58	256	0.490		
59	257/1	0.567		
60	257/2	0.465		
61	255	0.500		
62	269/1/2/3	0.007		
63	269/1/2/4	0.105		
64	254/2	0.488		
65	254/3	0.020		
66	254/4	0.033		
67	254/6	0.099		
68	242/2	0.169		
69	242/1/2	0.007		
70	198/1	0.042		
71	261	0.088		
72	260	0.876		
73	267	0.102		
74	268	0.079		
कुल रकबा		20.002		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9978-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0014-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 30 नवम्बर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	8.722 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- घड़िया

(ग) ग्राम

:- रामडिया

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 8.722 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	432	0.142	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	431	0.444		
3	427	0.485		
4	428	0.122		
5	406	0.200		
6	409	0.008		
7	408	0.242		

8	403/1	0.163		
9	403/2	0.014		
10	407	0.020		
11	405	0.030		
12	402	0.236		
13	412	0.103		
14	211	0.538		
15	209	0.203		
16	187	0.067		
17	188	0.090		
18	190	0.098		
19	193/1	0.434		
20	191	0.125		
21	194/1	0.155		
22	194/2	0.071		
23	192	0.253		
24	163	0.127		
25	161	0.532		
26	160	0.044		
27	148	0.452		
28	149	0.053		
29	150	0.099		
30	151	0.351		
31	152	0.040		
32	153/1	0.088	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
33	93/1	0.027		
34	93/2	0.079		
35	92/2	0.105		
36	88	0.680		
37	89/1	0.223		
38	87/1	0.080		
39	87/2	0.146		
40	87/3	0.145		
41	87/4	0.124		
42	87/5	0.112		
43	87/6	0.102		
44	81	0.870		
कुल रकबा		8.722		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9977-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0015-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक चार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यत निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	17.463 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| (क) जिला | :- उज्जैन |
| (ख) तहसील | :- घटिया |
| (ग) ग्राम | :- आजमपुरा |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 17.463 हेक्ट. |

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	500	1.085	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेल्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	502/2/2	0.001		
3	502/3	0.413		
4	498	0.057		
5	503/1	0.362		
6	503/2	0.726		
7	505/1	0.136		
8	505/2	0.180		
9	504/1/1	0.061		
10	504/1/2	0.274		
11	504/2	0.416		
12	504/3	0.019		
13	492/1	0.099		
14	492/2	1.070		
15	497	0.129		
16	490/1	0.344		
17	490/2	0.016		
18	491	0.374		
19	453	0.067		
20	446/1	0.369		
21	446/2	0.042		
22	446/3	0.002		
23	445	0.317		
24	443/1	0.011		
25	443/2	0.014		
26	400	0.083		
27	402/2	0.020		
28	402/3	0.128		
29	414/2	0.042		
30	413/2	0.067		
31	409/2	0.009		
33	395/2	0.306		
34	394/1/1	0.212		
35	394/1/2	0.176		
36	391	0.057		
37	392/1	0.328		
38	390/1	0.037		

39	389	0.071	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
40	388	0.101		
41	385	0.011		
42	69	0.200		
43	70	0.062		
44	75/1	0.098		
45	75/2	0.316		
46	76/1	0.431		
47	76/2	0.215		
48	76/3	0.123		
49	76/4	0.051		
50	92/1	0.086		
51	92/2	0.325		
52	103/3	0.162		
53	103/2/1	0.009		
54	90/1	0.148		
55	90/2	0.144		
56	88	0.146		
57	89	0.868		
58	230	0.570		
59	229/1	0.315		
60	229/2	0.051		
61	228	0.785		
62	238	0.476		
63	221	0.002		
64	220	0.216		
65	239/2	0.014		
66	212/1	0.308		
67	212/2	0.142		
68	210/1	0.041		
69	210/2	0.091		
70	209	0.193		
71	202	0.034		
72	203	0.322		
73	204	0.172		
74	200	0.203		
75	199	0.745		
76	247	0.926		
77	248	0.240	संभागीय प्रबंधक म.प्र. - सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
78	251	0.001		
कुल रकबा		17.463		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घड़िया के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घड़िया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9976-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0053-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	13.379 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	: उज्जैन
(ख) तहसील	: खाचरोद
(ग) ग्राम	: भाटखेड़ी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	: 13.379 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	36	0.048		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	22/1	0.281	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
3	22/2	0.550		
4	29	0.224		
5	28	0.763		
6	27	0.010		
7	32	0.003		
8	26	0.598		
9	38/1	0.336		
10	398/1	0.275		
11	398/2	0.225		
12	397/1	0.234		
13	397/2	0.215		
14	391	0.220		
15	393	0.194		
16	394/1	0.286		
17	394/2	0.433		
18	419/1	0.062		
19	420	0.123		
20	442	0.261		
21	443/5	0.445		
22	445/2	0.001		
23	446	0.289		
24	447	0.258		
25	449/1	0.012		
26	449/2	0.181		
27	450	0.336		
28	451	0.010		
29	481	0.020		
30	480	0.450		
31	479/1	0.010		
32	478	0.198		
33	486/2	0.308		
34	477	0.572		
35	489/1	0.828		
36	489/2	0.204		
37	474/2	0.077		
38	515	0.163		
39	514	0.091		
40	513	0.254		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
41	512	0.010		
42	511/1	0.030		
43	510/1	0.005		
44	494	0.621		
45	504/1	0.391		
46	504/2	0.381		
47	504/3	0.050		
48	595/1	0.072		
49	595/2	0.561		
50	597/1	0.342		
51	597/2	0.408		
52	598/2	0.006		
53	598/3	0.204		
54	599/1	0.010		
55	21	0.010		
56	399/2	0.230		
कुल रकबा		13.379		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9975-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0056-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	10.075 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- खाचरोद
(ग) ग्राम	:- बन्जारी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 10.075 हेक्ट

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	810/1/2	0.012		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	810/2	0.319	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
3	811/1	0.170		
4	811/2	0.276		
5	809/1	0.096		
6	812	0.328		
7	815	0.264		
8	814	0.331		
9	823/1	0.126		
10	823/2	0.002		
11	822	0.512		
12	821	0.534		
13	820	0.214		
14	828/2	0.082		
15	829	0.640		
16	830	0.218		
17	832/2	0.080		
18	831	0.650		
19	834	0.058		
20	835	0.088		
21	738/2	0.043		
22	848	0.667		
23	849/1	0.380		
24	849/2	0.190		
25	849/3	0.110		
26	846	0.210		
27	859	0.543		
28	850/1	0.051		
29	858/1	0.034		
30	874	0.674		
31	875	0.150		
32	878	0.030		
33	873/1	0.020		
34	873/2	0.020		
35	873/3	0.030		
36	872	0.070		
37	871/2	0.030		
38	871/3	0.060		
39	871/4	0.190		
40	870/2	0.001		
41	870/1	0.098		
42	867	0.010		
43	866	0.003		
44	879	0.373		
45	880	0.676		
46	881	0.300		
47	882/17	0.112		
कुल रकबा		10.075		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9974-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0052-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	13.485 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :- उज्जैन
 (ख) तहसील :- खाचरोद
 (ग) ग्राम :- चौकी जुनादा
 (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 13.485 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	5	0.287		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	18/1	0.306	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
3	18/2	0.170		
4	17	0.187		
5	16	0.020		
6	13	0.476		
7	10	0.482		
8	9	0.622		
9	8	0.125		
10	200	0.235		
11	199	0.444		
12	12	0.049		
13	198	0.643		
14	204/1	0.009		
15	197	0.725		
16	214/1	0.164		
17	190	0.505		
18	217	0.332		
19	218/1/1	0.041		
20	218/1/2	0.233		
21	218/2	0.002		
22	216/1	0.003		
23	216/2	0.058		
24	216/3	0.069		
25	220	0.300		
26	219	0.097		
27	222	0.207		
28	223/1	0.697		
29	223/2	0.153		
30	224/1	0.381		
31	224/2	0.005		
32	224/3	0.025		
33	234	0.064		
34	250/1	0.018		
35	250/2	0.294		
36	251	0.130		
37	253/1	0.007		
38	253/2	0.001		
39	338/1	0.128		
40	338/2	0.014		
41	335/1	0.02		
42	335/2	0.046		
43	335/3	0.163		
44	337	0.111		
45	332	0.336		
46	334/1	0.001		
47	375	0.020		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
48	331/2	0.005	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
49	331/3	0.002		
50	331/4	0.321		
51	331/5	0.028		
52	330/1	0.010		
53	330/2	0.258		
54	323/3	0.010		
55	323/4	0.194		
56	323/5	0.102		
57	323/6	0.054		
58	324	0.092		
59	328	0.219		
60	329/1/1	0.005		
61	329/1/2	0.012		
62	329/2	0.001		
63	325/1	0.013		
64	325/2	0.264		
65	315/1	0.326		
66	315/2	0.003		
67	428/1	0.326		
68	428/2	0.001		
69	429/1	0.066		
70	429/2	0.223		
71	424	0.329		
72	423	0.639		
73	421	0.472		
74	422	0.087		
75	574	0.018		
कुल रकबा		13.485		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9973-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0047-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समादात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	2.621 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- खाचरोद

(ग) ग्राम

:- बुरानाबाद

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 2.621 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	940/1	0.061	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	940/2	0.354		
3	945	0.170		
4	942	0.326		
5	946/1/1	0.050		
6	946/1/2	0.002		
7	943	0.300		
8	944/1	0.167		
9	944/2	0.220		
10	948	0.552		
11	952	0.419		
कुल रकबा		2.621		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9972-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0050-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हेड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हेड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हेड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	13.600 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला :- उज्जैन
 (ख) तहसील :- खाचरोद
 (ग) ग्राम :- दुमणी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 13.600 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	34	1.061		

क्र० स०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	46/1	0.074	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्ग्रुटी मॉडल
3	46/2	0.440		
4	47	0.383		
5	41	0.196		
6	51	0.805		
7	56	0.559		
8	65	0.386		
9	66	0.140		
10	57/1	0.120		
11	64/1	0.708		
12	64/2	0.095		
13	71/1	0.834		
14	72	0.923		
15	70	0.074		
16	73	0.764		
17	77	0.077		
18	90	0.496		
19	91	0.607		
20	88	1.438		
21	42/1	0.550		
22	42/2	0.498		
23	43	0.359		
24	35/1	0.145		
25	35/2	0.182		
26	35/3	0.133		
27	35/4	0.100		
28	33/1	0.280		
29	33/2	0.154		
30	32	0.155		
31	31/1	0.102		
32	31/2	0.048		
33	30/1/1	0.104		
34	30/1/2	0.131		
35	30/2	0.065		
36	4	0.251		
37	3/2	0.029		
38	3/1	0.086		
39	2	0.034		
40	45	0.014		
कुल रकबा		13.600		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9971-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0046-अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधियहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समानता निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	4.266 हेक्टर

-अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- खाचरोद

(ग) ग्राम

:- भीकमपुर

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 4.266 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	906/5	0.250		
2	910	0.159		
3	909	0.531		
4	907	0.098		
5	908	0.081		
6	932	0.115		
7	934	0.096		
8	935	0.222		
9	937	0.220		
10	936	0.374		
11	923/1	0.667		
12	923/2	0.025		
13	922	0.213		
14	926	0.300		
18	925/4	0.038		
19	924	0.016		
20	915	0.130		
21	916	0.646		
22	914	0.085		
कुल रकबा		4.266	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आवेदो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9970-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0057-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	19.071 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- खाचरोद
(ग) ग्राम	:- पचलासी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 19.071 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	506/1	0.078		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	506/3	0.124	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
3	506/4/1	0.287		
4	504/5	0.063		
5	504/3	0.014		
6	504/4	0.184		
7	504/6	0.305		
8	503	0.022		
9	502	0.236		
10	509/1	0.384		
11	508	0.001		
12	509/2	0.037		
13	499/2	0.002		
14	496/1	0.349		
15	498	0.046		
16	497	0.242		
17	496/2	0.192		
18	516/1/2	0.007		
19	494/1	0.021		
20	495	0.338		
21	517/1/1	0.675		
22	517/2	0.029		
23	517/1/2	0.038		
24	544	0.062		
25	518/1	0.155		
26	518/2	0.007		
27	543	0.903		
28	542	0.043		
29	541/1	0.019		
30	541/2	0.031		
31	538	0.152		
32	540	0.015		
33	537	0.144		
34	534	0.108		
35	533/1	0.010		
36	533/2	0.039		
37	550/2	0.076		
38	550/1	0.234		
39	532	0.002		
40	561	0.135		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
41	562	0.067	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
42	563	0.085		
43	564	0.089		
44	565	0.210		
45	566	0.064		
46	560	0.670		
47	567	0.097		
48	568	0.177		
49	570/1	0.177		
50	570/2	0.080		
51	569	0.030		
52	571/2	0.658		
53	575	0.103		
54	576/1/1	0.177		
55	576/1/2	0.053		
56	576/1/3	0.090		
57	576/2/1	0.350		
58	576/2/2	0.040		
59	576/3	0.096		
60	578/2	0.033		
61	578/1	0.156		
62	611/1	0.062		
63	611/2	0.207		
64	611/3	0.169		
65	577/1	0.074		
66	608	0.108		
67	609	0.289		
68	610	0.096		
69	607	0.004		
70	622	0.324		
71	621	0.135		
72	620	0.055		
73	623	0.111		
74	624	0.286		
75	625	0.131		
76	628	0.552		
77	835/1	0.020		
78	835/2	0.020		
79	834	0.020		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
80	833	0.020	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्कड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
81	832	0.010		
82	831	0.037		
83	830	0.001		
84	828	0.095		
85	836	0.445		
86	839/2	0.034		
87	838	0.035		
88	837	0.197		
89	825	0.032		
90	824	0.127		
91	851	0.055		
92	823	0.195		
93	852	0.285		
94	853	0.452		
95	854	0.007		
96	815/2	0.177		
97	817	0.012		
98	901/1	0.211		
99	901/3	0.078		
100	901/2	0.223		
101	902	0.342		
102	904/1	0.180		
103	904/2	0.404		
104	905/1	0.125		
105	905/2	0.027		
106	911/2	0.047		
107	911/3	0.080		
108	911/4	0.080		
109	910	0.022		
110	909	0.116		
111	907/6	0.133		
112	907/5	0.438		
113	908	0.180		
114	892/2	0.015		
115	892/1	0.112		
116	907/4, 907/3	0.812		
117	1846	0.134		
118	1847	0.001		
119	1845/2	0.447		
120	1844	0.612		
121	1843	0.062		
कुल रकबा		19.071		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 06-अ-82-2022-23-झिरियाडोह-10059

बैतूल, दिनांक 30 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची -1

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	चिचोली	झिरियाडोह	29.071	मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन

**अनुसूची -2
(धारकों की सूची)**

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	गरबसिंग व. सुखराम, जाति कोरकू भूमि स्वामी	12	1.702	1.702
2	श्रीराम व. भूरालाल, जाति कोरकू, भूमि स्वामी	13	1.619	1.619
		56	0.404	0.032
3	मंगल, फागू, फगना व. बब्बू, जाति कोरकू, भूमि स्वामी	16	0.405	0.195
		17	1.377	1.21
4	किसन, किशोरीलाल व. सम्मू, बिस्सो पुत्री सम्मू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	58	0.909	0.909
5	रामदास, रामविलास, कुडडा व. इमरत, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	57	0.545	0.545
6	देवजी व. समलू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	4	1.068	1.068
		15	0.583	0.403
7	जुगनी पुत्री धनाराम, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	5	1.801	1.583
		7	0.162	0.162
		27	0.47	0.12
8	बिहारीलाल व. राधेलाल, रुखमा बेवा मोहनसिंग, तुगना, दुजिया पुत्री प्यारेलाल	37	0.405	0.079

9	रामसिंह व. बिसना, रायसिंग, रमेश, बिसोरी, कस्तूरी, अंतरा, ना.बा. वली बिसना, बुद्ध व. बिरजलाल, बिरजलाल व. बिरजलाल, संतरी पुत्री बिरजलाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	6	0.121	0.121
		9	0.966	0.966
		14	1.437	0.924
		39	0.393	0.151
10	सखाराम व. दमडू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	10	0.809	0.809
11	बज्जू व. भैयालाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	8	2.426	0.925
12	जुगनी पत्नी मंगूलाल, दुजिलय पत्नी सदोजी, बिहारी व. राधेलाल, जाति कोरकू भूमिस्वामी	11	0.902	0.902
13	बिहारीलाल व. राधेलाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	19	1.214	0.13
14	बिसराम, बिसनू व. किसना, रमोती बेवा किसना, हजारी व. कन्हैया, बुद्धो पुत्री कन्हैया, किशोरीलाल व. श्यामलाल, जुगिया बेवा श्यामलाल, दुल्लो, घुडू पुत्री श्यामलाल, कैलाश व. साबू, झबिया बेवा साबू, सुगरती, सुगंति, सुगरती, सुमनतारा पुत्री साबू, अशोक व. सरदार, चंद्रकली पुत्री सरदार, शिवकली पुत्री सरदार, रामकली पुत्री सरदार, रामसिंग, अमरसिंग, सुरेसिंग, पुनेसिंग, सूरतराम व. सागर, मुसिया बेवा सागर, मुन्नी पुत्री सागर, मंगली, कंगली पुत्री समलू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	18	0.34	0.229
		33	0.85	0.85
		34	0.146	0.146
		32	0.555	0.54
		22	2.08	0.407
		68	0.324	0.301
		69	1.076	1.076
15	शिवप्रसाद व. चौबे, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	35	0.223	0.2
16	भूरी पुत्री रामा, श्यामू पुत्र सूका, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	31	0.117	0.107
17	श्यामलाल व. शिवलाल, रेवालाल, बुद्धो, कन्ना व. भादू, मुशीलाल, सुरतसिंग, रामसिंग व. छोटे, जुगनी, मुंगिया पुत्री छोटे, बंसती, संतो, सनतिया, बिसन्या व. दादू, रमोती पुत्री मंगल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	30	0.251	0.251
18	जगन्नाथ व. सालकराम, हीरालाल व. लिमिया, जाति चम्हार, भूमिस्वामी	28	0.162	0.065
19	चतरसिंग, अनारसिंग, विजेन्द्र, विजय व. छोटे, बैजी पुत्री छोटे, छोटे व. रामबकस, समोती पुत्री रामबकस, परसू व. बुद्ध, ओझू, भोजू, मंगल व. मोरे, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	26	0.166	0.066
20	सुखलाल बुकलाल बुक्कू वल्द बज्जू, नर्मदा पुत्री रज्जू, मोहनसिंग व. रज्जू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	38	0.267	0.057
21	कमला बेवा ब्रजलाल, अमरसिंग, सुरेसिंग व. ब्रजलाल, रामप्रसाद उरफ शिवप्रसाद, रामदयाल व. पतिराम, रामरती बेवा चिरौजीलाल, डोंगरसिंग व. चिरौजीलाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	75	0.283	0.283
22	प्रेमसिंग व. तेजीलाल, फुलवती बेवा रामसिंग, लक्ष्मण व. रामसिंग, वर्षा पुत्री रामसिंग, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	99	0.595	0.048

23	प्रेमसिंग व. तेजीलाल, फुलवती बेवा रामसिंग, लक्ष्मण व. रामसिंग, वर्षा पुत्री रामसिंग, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	100/1	2.034	0.024
24	अमरसिंग, जयसिंग, सुखराम व. बेजीलाल, मंगा, सुमरती पुत्री बेजीलाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	100/2	0.459	
25	कोदूलाल व. जंगली, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	100/3	1.586	
26	देवजी, श्रीराम, रामगोपाल, पिरथीलाल व. समलू, संतिया पुत्री समलू, मंतो संतो पुत्री समलू, जीरो बेवा रमलू, परसू, चम्पू व. रमलू, भगरई मांगो व. रमलू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	101	3.586	3.586
27	रामलाल, सायबा, सदाराम, सोबू व. श्यामलाल, झरौ पुत्री श्यामलाल, मुंगई, मुन्नी पुत्री श्यामलाल, रजली बेवा कारमू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	103/1	3.742	2.382
28	देवजी, श्रीराम, रामगोपाल, पिरथीलाल व. समलू, संतिया, मंतो, संतो पुत्री समलू, जीरो बेवा रमलू, परसू, चम्पू व. रमलू, भगरई, मांगो पुत्री रमलू, जाति कोरकू भूमिस्वामी	103/2	0.155	
29	रामचरण व. भंगी, रमको पुत्री भंगी, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	105	1.781	0.91
		106	2.124	0.503
30	मंगल, मंगलू, किसनलाल व. जग्गू, गजरी बेवा जग्गू, बसंती, तिपा, जग्गू, प्रेमसिंग, प्रयागसिंग व. मोतीराम, मुन्नी, चुन्नीलाल, चल्लूसिंग, चुलूमसिंग व. चैतू, बन्नूलला, बटूलाल, सददूलाल, छत्रपाल, पिरथीलाल चेताराम, सुरतराम व. सुक्कू, बतसिया, बिस्तोरी व. सुक्कू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	166	5.326	1.082
31	ओझू व. मंदू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	165	1.402	0.741
32	रुनिया बेवा बंतू, संतरी पुत्री बंतू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	167	0.606	0.364
33	बटू पुत्र सुका, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	168	2.023	0.298
योग			51.977	29.071

(2) चूंकि मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2024

क्रमांक.: F-6-0009/2024/सात/शा.-7 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार शाजापुर जिले के तहसील शाजापुर की सीमाओं को परिवर्तित करने नवीन तहसील "मक्सी" सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

2/ "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रहित किए जा सकेंगे। :-

अनुसूची

अनु. क्र.	विद्यमान तहसील का नाम और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किए गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील की सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1.	तहसील शाजापुर (मुख्यालय शाजापुर)	वर्तमान तहसील शाजापुर के पटवारी हल्का न. 155 से 165 तक कुल 11 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे।	तहसील शाजापुर मुख्यालय शाजापुर	वर्तमान तहसील शाजापुर के पटवारी हल्का न. 101 से 154 एवं 166 से 180 तक कुल 69 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	पूर्व - तहसील गुलाना पश्चिम - जिला उज्जैन उत्तर - तहसील मोमन बडोदिया दक्षिण - प्रस्तावित तहसील मक्सी
2.	-	-	तहसील मक्सी मुख्यालय मक्सी	वर्तमान तहसील शाजापुर के पटवारी हल्का न. 155 से 165 तक कुल 11 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	पूर्व - तहसील शाजापुर पश्चिम - जिला उज्जैन उत्तर - जिला उज्जैन दक्षिण - जिला देवास

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2024

क्र.-A-7510-दो-2-22-2022.-श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-A-7512-दो-2-7-2019.-श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 23 से 25 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-A-7514-दो-2-12-2024.-श्री उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 19 से 20 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश पाण्डव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-7516-दो-2-28-2019.-श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 24 से 25 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-7523-दो-2-82-2020.-श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-7525-दो-3-420-80-भाग-बारह.- डॉ. शिवकुमार मिश्र, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024

Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार - श्री मिश्र की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को उनके खाते में 240 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 474 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज — 240 दिवस में नगद भुगतान.
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज — 120/2= 60 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

क्र.-A-7527-दो-3-420-80-भाग-बारह.- डॉ. शिवकुमार मिश्र, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए-2471, दिनांक 7 नवम्बर 2020 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-A-7529-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री प्रदीप कुमार व्यास, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2013, दिनांक 19 मई 2020 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-A-7531-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री प्रदीप कुमार व्यास, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में

लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार-श्री व्यास की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2020 को उनके खाते में 269 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 608 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज — 269 दिवस में नगद भुगतान
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज — 62/2= 31 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-A-7534-दो-2-24-2024.-श्री मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-7537-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री कैलाश चन्द्र यादव, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2018 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-5684, दिनांक 13 अगस्त 2018 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-A-7539-दो-3-420-80-भाग-बारह.-श्री कैलाश चन्द्र यादव, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री यादव की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2018 को उनके खाते में 202 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 390 अर्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज - 202 दिवस
में नगद भुगतान.

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - 196/2= 98
में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण
अवकाश वेतन).

क्र.-A-7541-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री हरिशंकर वैश्य, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-973, दिनांक 10 फरवरी 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक -643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-A-7543-दो-3-420-80-भाग-बारह.-श्री हरिशंकर वैश्य, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन

विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री वैश्य की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को उनके खाते में 167 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 432 अर्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज - 167 दिवस
में नगद भुगतान.

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - 266/2= 133
में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण
अवकाश वेतन.

जबलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2024

क्र.-C-7422-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री ए. के. पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2016 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-971, दिनांक 10 फरवरी 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-C-7425-दो-3-420-80-भाग-बारह.-श्री ए. के. पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका

क्रमांक— (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार— श्री पाण्डेय की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2016 को उनके खाते में 161 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 350 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज — 161 दिवस में नगद भुगतान.
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज — 278/2= 139 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-A-7574-दो-2-35-2023.—श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 14 से 17 अक्टूबर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-7576-दो-2-23-2020.—श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-7578-दो-2-40-2019.—श्री अभिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 25 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.-A-7580-दो-2-20-2021.—श्री एस. के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-7426-दो-3-420-80-भाग-बारह.— श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2015, दिनांक 19 मई 2020 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-C-7428-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री दीक्षित की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2020 को उनके खाते में 223 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 338 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज - 223 दिवस
में नगद भुगतान.
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज - $134/2 = 67$
में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण
अवकाश वेतन.

क्र.-C-7430-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक-(i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री रघुवंशी की सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2017

को उनके खाते में 234 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 568 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज - 234 दिवस
में नगद भुगतान.
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज - $132/2 = 66$
में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण
अवकाश वेतन.

क्र.-C-7430-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई-2829, दिनांक 12 अप्रैल 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-C-7434-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री एस. के. शर्मा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री शर्मा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 1 दिसम्बर 2020 को उनके खाते में 205 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 566 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज - 205 दिवस
में नगद भुगतान.
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज - $190/2 = 95$
में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण
अवकाश वेतन.

क्र.-C-7436-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री एस. के. शर्मा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 1 दिसम्बर 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए-574, दिनांक 25 फरवरी 2021 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

क्र.-C-7440-दो-2-31-2018.-श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 2 से 6 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-7442-दो-2-22-2023.-श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक, 12 माह की अवधि के लिए पन्द्रह दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-C-7444-दो-2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 6 मई 2024 का एवं दिनांक 8 से 10 मई 2024 तक का कुल चार दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 6 से 10 मई 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सैय्यदुल अबरार अंसारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-7446-दो-2-62-2016.-श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 11 से 12 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-7448-दो-2-62-2016-श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 21 एवं 20 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-4906-दो-2-19-2024.-श्री रूपेश शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 14 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.-B-4908-दो-2-62-2016.-श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 2 से 4 सितम्बर 2024 तक, कुल तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-4910-दो-2-26-2022.-श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ को दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 अनुग्रह वर्ष (ग्रेस ईयर) अक्टूबर, 2024 तक की अवधि के लिये एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2023 से 2027 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक), 2011 दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.-B-4912-दो-2-22-2023.-श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ब्लाक वर्ष 2022 से 2024 तक की ब्लाक अवधि के लिये एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)

19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक), 2011 दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.-B-4914-दो-2-36-2021.-श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-4916-दो-2-64-2014.-श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 21 से 22 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-4918-दो-2-13-2010.-श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-4946-दो-2-52-2021.-श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 8 से 21 अक्टूबर 2024 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-B-4948 -दो-2-53-2022.- श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 27 से 28 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
2. दिनांक 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-4950-दो-2-41-2017.-श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 14 से 15 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-4954-दो-2-2-2023.-श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 8 से 22 अक्टूबर 2024 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-4956-दो-2-35-2020.-श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-4952-दो-2-16-2010.-श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 11 से 14 नवम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 नवम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-4891-दो-2-40-2018.-श्री जाकिर हुसैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जाकिर हुसैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जाकिर हुसैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-7438-दो-2-43-2020.-श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 11 से 14 नवम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2024

शुद्धि-पत्र

क्र.-C-7583-दो-3-420-80-भाग-बारह.-श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को आदेश क्रमांक सी-7426, दिनांक 23 अक्टूबर 2024 की आदेश की कंडिका क्रमांक (ii) में टंकण की त्रुटिवश अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान : $134/2 = 67$ दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन लेख हो गया है, जबकि कंडिका क्रमांक (ii) में अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान : $154/2 = 77$ दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन लिखा जाना था।

अतः उक्त आदेश को निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

- | | | | |
|------|-------------------------|---|---------------|
| (i) | अर्जित अवकाश के एवज | — | 223 दिवस |
| | में नगद भुगतान. | | |
| (ii) | अर्धवेतनिक अवकाश के एवज | — | $154/2 = 77$ |
| | में नगद भुगतान. | | दिवस का पूर्ण |
| | | | अवकाश वेतन. |

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.-कम-पी. पी. एस.